

निकिता तोमर मामले में फिर राजनीति, अब भाजपाई नेता निशाने पर

कुछ लोगों और संगठनों ने इसकी आड़ में तलाशा 'चंदा बटोरो' अभियान



निकिता तोमर

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में फिर से राजनीति शुरू हो गई है। निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने 3 जनवरी को "समाज" की बैठक बुलाई थी। उसमें गिनती के लोग पहुँचे। लेकिन उसमें केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा को सीधे निशाने पर लिया गया।

इस बैठक के खत्म होते-होते दो और लोग भी पहुँचे, जिनकी गतिविधियों का संज्ञान लेना जरूरी है। ये हैं - आरएसएस से जुड़ा पोर्टल "स्वराज्यमैग" चलाने वाली स्वाति गोयल शर्मा और संजीव नेवर पहुँचे। संजीव और स्वाति एनजीओ "सेवा न्याय उत्थान" फ़ाउंडेशन के संस्थापक हैं। यह एनजीओ भी अघोषित रूप से आरएसएस से सम्बद्ध है। ये लोग अब इस मामले में एक्शन कमेटी बनवाकर मामले को फिर से जिन्दा करना चाहते हैं।

निकिता तोमर मामले को गृहमंत्री अनिल विज ने "लव जिहाद" बता डाला था लेकिन जब पुलिस ने 60 गवाहों के साथ 700 पेजों की चार्जशीट पेश की तो उसमें लव जिहाद का दूर दूर तक जिक्र नहीं था।

पहले पूरी घटना को जानिए

अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर 2020 को निकिता तोमर की गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में चौबीस घंटे के अंदर निकिता के दोस्त तौसीफ और उसके साथी रेहान को मेवात से गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा कथित अभियुक्त अज्जू बाद में पकड़ा गया।

निकिता की हत्या के बाद भाजपाई और संघ से जुड़े संगठनों ने इसे हिन्दू-मुस्लिम मामला बनाने में देर नहीं लगाई। इसके नाम पर बल्लभगढ़ में उपद्रव की कोशिश हुई लेकिन पुलिस ने समझदारी से हालात को काबू कर लिया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जब वहाँ हमदर्दी जताने पहुँचीं तो भाजपाई पार्षद के नेतृत्व में अराजक तत्वों ने कुमारी शैलजा से बदसलूकी की।

निकिता के पिता मूलचंद तोमर के घर पर केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा समेत भाजपा व संघ के कई नेता पहुँचे। वहाँ हुई महापंचायत में निकिता के परिवार से नेताओं ने कई वादे किए। जिसमें परिवार को एक करोड़ की आर्थिक मदद, भाई को सरकारी नौकरी और किसी कॉलेज का नाम निकिता के नाम पर रखने की माँग की गई थी।

निकिता के पिता की हताशा

निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि इस केस में चल रहे मुकदमे में भागदौड़ की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं कि इस मामले को



निकिता के पिता के साथ पत्रकार स्वाति गोयल

आगे बढ़ा सकूँ। जिन लोगों ने जो वादे किए थे, उसमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जो लोग उस समय साथ खड़े थे, वे अब सहयोग नहीं कर रहे हैं। मूलचंद तोमर की इस अपील के साथ अपना घर सोसायटी के पास एक वाटिका में "समाज" की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दो सौ लोगों के जुटने का वादा किया गया लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोग उस संख्या में नहीं जुटे, जितनी बड़ी संख्या में वे निकिता तोमर की हत्या के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपद्रव करने के लिए जुटे थे।

"समाज" की बैठक में मूलचंद तोमर ने केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाया कि वो जब शुक्रवार (1 जनवरी 2021) को मिलने गए तो मंत्री को एसआईटी जाँच की प्रगति की कोई जानकारी नहीं थी। ना ही उन्होंने अपने पुराने वादों के बारे में कोई भरोसा दिया।

इस बैठक में निकिता के चाचा हाकिम सिंह ने आरोप लगाया कि हमारे परिवार को स्थानीय सांसद (कृष्णपाल), स्थानीय विधायक (मूलचंद शर्मा) और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आश्वासन दिया था कि हर तरह से पूरी मदद की जाएगी लेकिन आज 70 दिन बीतने के बावजूद दूर-दूर तक मदद नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इस मामले में पुलिस मुख्य मुलाजिम तौसीफ समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक अदालत में चल रही है। इसके बावजूद निकिता का परिवार अभी भी इंसफ नहीं मिलने का आरोप लगा रहा है।

राजनीतिक रूप लेता मामला

सूत्रों का कहना है कि जिस तरह निकिता तोमर के परिवार का इस्तेमाल इस मामले को साम्प्रदायिक रंग देने के लिए हिन्दू संगठनों के नेताओं ने किया, अब कतिपय राजनीतिक लोग इस मामले को तूल देना चाहते हैं। 3 जनवरी की बैठक में जिस तरह निकिता के पिता और चाचा के तेवर में राजनीतिक रंग था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस परिवार में इतना साहस नहीं है कि वो केन्द्रीय मंत्री और हरियाणा के मंत्री पर इस तरह निशाना साध सके। जरूर उन्हें कुछ राजनीतिक लोग ही गाइड कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के सामने दुविधा यह

है कि वो अगर इस तरह के अपराधों में पीड़ित लोगों को लाखों का मुआवज़ा और नौकरी देती फिरगी तो उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा। जिन्हें नहीं मिलेगा, वे अदालत में इस मामले के आधार पर याचिकाएँ दायर कर सकते हैं।

चंदा बटोरने का सॉलिड जुगाड़

निकिता तोमर मामले में हिन्दू अस्मिता की दुहाई देकर कुछ लोग समाज से चंदा बटोरने का जुगाड़ कर रहे हैं। इस संबंध में ऐसे पर्चे भी सामने आए हैं जिसमें निकिता के परिवार के लिए पैसा माँगा गया है।

लेकिन 3 जनवरी को मूलचंद तोमर से हमदर्दी जताने पहुँची पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा और संजीव नेवर ने सीधे-सीधे इस केस का हवाला देकर अपने एनजीओ सेवा न्याय उत्थान फ़ाउंडेशन के ज़रिए पैसे की मदद माँगी। इस संवाददाता के पास इस बात के सुबूत हैं कि दोनों ने अपने एनजीओ का खाता नंबर और आईएफसी कोड देते हुए आर्थिक मदद माँगी।

एनजीओ संस्थापक और पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा ने अपनी अपील में लिखा है कि निकिता के पिता मूलचंद तोमर जैसे लोगों के पास लीगल और फ़ाइनेंशियल मदद का कोई ईको सिस्टम नहीं है। इसलिए हम अपने एनजीओ "सेवा न्याय उत्थान" के ज़रिए उनकी (तोमर परिवार) लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमारी मदद करें। इसके बाद खाता नंबर और ई-मेल आईडी दी गई है ताकि रसीद ईमेल पर भेजी जा सके।

इसके फ़ौरन बाद आरएसएस के विचारक और पत्रकार तरुण विजय ने इसका समर्थन करते हुए हिन्दूओं को ललकारा। तरुण विजय ने इस अभियान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हिन्दूओं को दिखावटी चिन्ता का नाटक बंद करना चाहिए। तोमर जी की निराशा तो सामने आ गई। हज़ारों लोग इसी तरह खामोशी से सब सहते हैं। साइनबोर्ड वाले हिन्दू (यानी होडिंग लगाकर प्रचार करने वाले संघी व भाजपाई) हमेशा अपनी ही तारीफ़ में व्यस्त रहते हैं। मैं स्वाति को सैल्यूट करता हूँ कि वो एक रीढ़विहीन समाज की मदद कर रही हैं।

ज़ाहिर है कि संघ के इन दो स्वयंसेवकों स्वाति और संजीव नेवर की अपील पर तरुण विजय की प्रशंसा मुहर लगने के बाद निकिता तोमर के नाम पर चंदा तो

आना ही था। बड़े पैमाने पर लोग पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं।

लोग पाँच सौ रुपये से लेकर दो हज़ार तक की रसीदें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पैसे की राशि कितनी है, इसे मिटाकर रसीद शेयर की है। ये सभी पैसे स्वाति और संजीव के एनजीओ को सीधे जा रहे हैं। मूलचंद तोमर तक कब पहुँचेंगे, सवाल यही है। हालाँकि पत्रकार स्वाति ने मंगलवार (5 जनवरी) को कहा कि वह बुधवार को कुछ पैसा मूलचंद तोमर को देंगी। उनकी कोशिश होगी कि स्थानीय लोगों की एक एक्शन कमेटी बनाकर मामले को लड़ा जाए। इस चंदा जुगाड़ अभियान के ज़रिए एक बार फिर साम्प्रदायिक भावनाओं को भी भड़काया जा रहा है।

स्वाति गोयल शर्मा और संजीव नेवर का एनजीओ "सेवा न्याय उत्थान" फ़ाउंडेशन का दफ़्तर दक्षिणी दिल्ली के साकेत में है। एक किलो आटा और पाँच सौ ग्राम चीनी बाँटकर फ़ोटो छपवाने वाला

यह संगठन अपना आदर्श बाबा साहब आम्बेडकर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति स्व. एपीजे अब्दुल कलाम को मानता है। एनजीओ ग़रीबी मिटाने के दावे जोरशोर से करता है। लेकिन जैसे ही कोई पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा और संजीव नेवर के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेगा तो पता चलेगा कि दोनों धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।

संघी धंधेबाजों को चाहिये कि वे अपनी सरकार से एक कानून पास करवा लें जिसके अनुसार हर कत्ल होने वाले के परिजनों को कम से कम एक करोड़ रुपया व एक सरकारी नौकरी दी जायेगी। यह अगर बहुत ज्यादा लगे तो कम से कम उस मामले में तो इसे लागू करा ही दें जिसमें हत्या मुस्लिम व पीड़ित हिंदू हो। यह भी यदि भारी लगता हो तो उस मामले में तो लागू कराया ही जा सकता है जिसे राज्य के गृहमंत्री विज ने लव जिहाद का टाइटल दे दिया हो।

खबर मरम्मत

जुम्न मियां पंकर वाले

भक्तों को खुद ही भगवान का डर नहीं

खबर है कि इसाईयों के धर्मगुरु पोप ने पिछले दिनों अपने वित्त विभाग के कई अधिकारियों को काम से अलग कर दिया है। उन पर वैटिकन के वित्तीय प्रबन्धन में गड़बड़ी करने के आरोप काफ़ी समय से लगाये जा रहे थे। पोप इसाईयों के धर्मगुरु ही नहीं बल्कि वैटिकन राज्य के प्रमुख भी हैं। रोम में स्थित वैटिकन शहर को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त है जिसकी अपनी सरकार है।

धर्म राज्य के सबसे बड़े प्रतिष्ठान में भी पैसों की हेरा-फेरी और दोषियों के खिलाफ़ खुद भगवान द्वारा कोई कार्रवाई न करने बल्कि पोप द्वारा कार्रवाई करने को मजबूर होना दिखाता है कि न तो भक्तों को भगवान पर विश्वास है और न ही उसका डर। उनको स्पष्ट है कि भौतिक इच्छायें पूरी करने में भगवान मदद नहीं करेंगे बल्कि पैसा करेगा चाहे वो किसी भी तरह हासिल किया जाये। और पैसों की हेरा-फेरी में भगवान कोई दखल नहीं दे सकता चाहे वो सर्वव्यापी ही क्यों न हो।

श्मशान घाट में भी कमीशनखोरी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले में मुरादनगर नगर पालिका के अन्तर्गत आने वाला एक गांव में श्मशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की दब कर मौत हो गई। गलियारे की इस छत का निर्माण अभी 15 दिन पहले ही सम्पूर्ण हुआ था। इस सम्बन्ध में नगर पालिका की कार्यकारी अधिकारी निहारिका सिंह, जेई चन्द्र पाल, सुपरवाइजर आशीष और ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि 55 लाख से हुये निर्माण में ठेकेदार ने 16 लाख रुपये बतौर रिश्वत (कमीशन!) इन अधिकारियों को दिये थे। उधर मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी देने और आरोपियों पर रासुका लगाये जाने की घोषणा की है।

छोटे-मोटे शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों की तुरत-फुरत सम्पत्ति कुर्क करने वाले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इन सारे अफ़सरोँ और ठेकेदार की सम्पत्ति कुर्क करने की बात क्यों नहीं करते। बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार में रहमदिली क्यों है? क्यों नहीं ऐसे लोगों के मुकदमे त्वरित अदालतों में चलाकर जल्दी निपटायें जाये और इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाये।

हरियाणा में बेरोजगारी-600 पदों के लिए सात लाख आवेदन

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 9 व 10 जनवरी को ग्राम सचिवके 600 पदों के लिये परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में लगभग 6 लाख 72 हजार लोग बैठेंगे। यानी एक-एक पद के लिये लगभग एक हजार उम्मीदवार इसके लिये 17 जिलों में 879 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं।

इससे पहले हरियाणा सरकार अनेकों पदों के लिये आवेदन मांग चुकी है। किसी की परीक्षा ही नहीं हुई तो किसी की परीक्षा होने के बाद नियुक्ति नहीं की गई। नई नौकरी लगने की तो पता नहीं पर नौकरी से हटाने में सरकार की चुस्ती को कोई मात नहीं दे सकता चाहे वो मास्टर हो या पीटीआई या अन्य कर्मचारी।

अन्तिम मिसरा

किसान हैं इसलिये डटे हुये हैं,

विधायक होते तो कब के बिक चुके होते!